

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE (REVENUE) DEPARTMENT

DECISION OF THE GOVERNMENT

No. F4(36) FD/Rev./96-pt-1

Date:- 12 AUG 2010

Sub:-Payment of sum assured under Rajasthan Government
Servant Insurance Rules. 1998 in certain cases.

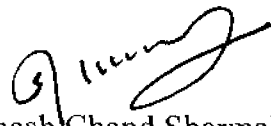
The decision circulated\issued earlier vide this department letter of even number dated 22.11.2007, is hereby substituted by the following with immediate effect :-

1. (i) Under Rule 51 of the Rajasthan Government Servants Insurance Rules, 1998 provision for payment of double sum assured has been made in case the insured dies before normal date of maturity of his policy. A doubt has been raised regarding payment of double of the sum assured in cases of the insured employees who go missing and are thereafter not heard of for at least seven years.
- (ii) The matter has been considered in the Government. An employee can also be presumed dead under law if he has not been seen / heard of for a period exceeding seven years, the Court declares such persons presumed to be dead under provisions of Evidence Act. It has been therefore decided that such legal deaths of government employees should also be taken as death under above referred insurance rules once a government employee is declared dead by a competent court of law.
- (iii) In view of above, it is clarified that in case of missing insured, if an order of competent court declares his/ her presumed death, the claim can be settled as follows:
 - (a) Double of the sum assured can be paid if normal date of maturity of his /her policy /assurances falls after the presumed date of death as per the orders of the Court i.e maturity of his policy should not be within seven years of his going missing.
 - (b) Payment of single sum assured, if normal date of maturity of his/her policy/ assurances falls before the date of presumed death as per orders of the Court i.e. his date of maturity of his policy should fall within seven years of his going missing.

2. Under rule 37 a provision exists for payment of sum assured to the nominee. An issue has arisen whether a nominee accused of the murder or abetting in murder of the insured, can be paid amount of sum assured.


The government has considered the circumstances and it is clarified as under :-

- (i) The payment of sum assured will be suspended till the conclusion of the criminal proceeding against nominee.
- (ii) If on the conclusion of the criminal proceeding referred to in para (i), the person concerned-
- (a) is convicted for the murder or abetting in the murder of the insured, he shall be debarred from receiving his claim, which shall be payable to other eligible members of the family, as per rule 38;
- (b) is acquitted of the charge of murdering or abetting in the murder of the insured, and if Government does not want to go in appeal, claim shall be payable to him.


(Subhash Chand Sharma)
Officer on Special Duty

Copy for information to :-

1. P.S. to all Principal Secretaries/Secretaries
2. All Head of Department.
3. Commissioner, State Insurance and P.F. Deptt.
4. System Analysts, Finance Department


12-8-10
Officer on Special Duty

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

सरकार का विनिश्चय

12 AUG 2010

क्रमांक प.4(36) वित्त/राजस्व/96 पार्ट-I

जयपुर, दिनांक

विषय:—कतिपय मामलों में राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम 1998 के अधीन बीमाकृत राशि का संदाय।

- (1) (i) राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम, 1998 के नियम 51 के अधीन ऐसे मामलों में, जिनमें बीमाकृत व्यक्ति अपनी पॉलिसी की परिपक्वता की सामान्य तारीख से पूर्व मर जाता है, बीमा राशि के दुगने के संदाय का उपबन्ध किया गया है। बीमाकृत कर्मचारी, जो लापता है और तत्पश्चात् कम से कम सात वर्ष की अवधि से उसके बारे में सुना नहीं गया है, के मामलों में बीमाकृत राशि के दुगने के संदाय से संबंधित एक संदेह उत्पन्न हुआ है।
- (ii) सरकार द्वारा इस मामले पर विचार किया गया। किसी कर्मचारी के मृत होने की विधि के अधीन उपधारणा तब भी की जा सकती है जबकि उसे सात वर्षों से अधिक अवधि के लिए देखा/सुना नहीं गया हो। साक्ष्य अधिनियम के उपबन्धों के अधीन न्यायालय ऐसे व्यक्तियों के मृत होने की उपधारणा करता है। इसलिए यह विनिश्चित किया गया है कि एक बार यदि किसी सरकारी कर्मचारी को सक्षम न्यायालय द्वारा मृत घोषित कर दिया जाये तो सरकारी कर्मचारियों की ऐसी विधिक मृत्यु को भी उपर्युक्त निर्दिष्ट बीमा नियमों के अधीन मृत्यु के रूप में लिया जाना चाहिए।

(2)

(iii) उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि बीमाकृत व्यक्ति के लापता होने की दशा में यदि सक्षम न्यायालय का कोई आदेश उसकी उपधारित मृत्यु की घोषणा करता है तो दावा निम्नानुसार स्थापित किया जा सकता है:-

(क) बीमाकृत राशि का दुगना संदत्त किया जा सकता है यदि उसकी पॉलिसी/समाश्वासनों की परिपक्वता की सामान्य तारीख न्यायालय के आदेशों के अनुसार मृत्यु की उपधारित तारीख के पश्चात् पड़ती है अर्थात् उसकी पॉलिसी की परिपक्वता उसके लापता होने के सात वर्षों के भीतर नहीं होनी चाहिए।

(ख) बीमाकृत राशि की एकल राशि का संदाय किया जा सकता है यदि उसकी पॉलिसी/समाश्वासनों की परिपक्वता की सामान्य तारीख न्यायालय के आदेशों के अनुसार उपधारित मृत्यु की तारीख से पूर्व पड़ती हो अर्थात् उसकी पॉलिसी की परिपक्वता की तारीख उसके लापता होने के सात वर्षों के भीतर होनी चाहिए।

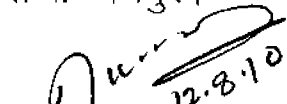


(सुभाष चन्द शर्मा)

विशेषाधिकारी, वित्त (बीमा/पेंशन)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त
2. निजी सचिव, समस्त प्रमुख शासन सचिव,
3. समस्त विभागाध्यक्ष,
4. आयुक्त, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राज. जयपुर।
5. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग।
6. रक्षित पत्रावली।



12.8.10
विशेषाधिकारी